



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941

No. 380]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

[मामला सं. (ओ.आई.) 21/2019]

**विषय – कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई तथा सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।**

**फा. सं. 6/29/2019—डीजीटीआर.**—जबकि मैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके पश्चात आवेदक के रूप में संदर्भित) ने कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई तथा सिगापुर (संबद्ध देशों के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ‘मोनो एथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी अथवा एथीलीन ग्लाइकोल)(इसके पश्चात “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” के रूप में संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “पाटनरोधी नियमावली” अर्थात् “नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष घरेलू उद्योग के माध्यम से एक आवेदन दायर किया है।

## विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल ” (एमईजी अथवा एथीलीन ग्लाइकोल) है। यह एक स्पष्ट, रंग रहित, वास्तविक रूप से गंध रहित और मामूली रूप से चिपचिपा तरल पदार्थ है। संबद्ध वस्तु का उपयोग पोलिएस्टर फाइबर, पोलिएस्टर फिल्म और रेजिन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र के फाइबर ट्रीटमेंट, कागज उद्योग और गोंद, स्याही तथा सेलफोन में भी किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में एक

निर्जलीकरण एजेंट के रूप में भी किया जाता है, जहां यह गैस से पुनः प्राप्त और पुनः उपयोग किए जाने के पूर्व प्राकृतिक गैस क्लैथरेट के निर्माण को रोकता है।

3. एमईजी का वर्गीकरण प्रशुल्क सीमाशुल्क वर्गीकरण 2905 31 00 के अंतर्गत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

### **समान वस्तु**

4. आवेदक ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की समान मद है। यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने यह दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी तौर पर और वाणिज्यिक रूप में प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग और आधार**

5. यह आवेदन मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है यह भी नोट किया जाता है कि मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कम मात्रा का आयात किया है। जिसके लिए संयंत्र को पूर्ण रूप से बंद करना तथा स्थानीय बाजार को सहायता प्रदान करना अपेक्षित है।

6. इस मामले की जांच की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा आयातों की कम मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के तात्पर्य से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है। यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

### **शामिल देश**

7. वर्तमान जांच कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यू.ए.ई और सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

### **सामान्य मूल्य**

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यू.ए.ई में विशेष बाजार की स्थिति मौजूद है क्योंकि उत्पादकों को अलग-अलग और छूट प्राप्त कीमतों पर मूलभूत फीड स्टॉक प्राप्त होता है। कच्चे माल की विपथित कीमतों के कारण, आवेदक ने यह दावा किया कि इस प्रकार की कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी लागतों को तर्कसंगत तरीके से नहीं दर्शाता है। तदनुसार, आवेदक ने दावा किया है कि कच्चे माल की लागत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार किया जाना चाहिए।

9. जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यू.ए.ई के लिए सामान्य मूल्य इसके प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर तय किया गया है। सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य की गणना आईसीआईएस प्रकाशित रिपोर्ट में उपलब्ध एशिया प्रशांत कीमतों के आधार पर की गई है।

### **निर्यात कीमत**

10. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन संबंधी खर्च, कमीशन और अंतर्देशीय भाड़े संबंधी खर्च के प्रति उचित समायोजनों के बाद किया गया है।

### **पाटन मार्जिन**

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत से की गई है प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं को भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन का निर्धारण न्यूनतम से अधिक के रूप में लगाया गया है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

12. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभावों, जैसे कीमत में कटौती और कीमत न्यूनीकरण, जिसके फलस्वरूप माल भंडार संचित हुआ, लाभ में गिरावट आई, नियोजित पूंजी पर लाभ में गिरावट और नकद लाभ में कमी हुई है, से देखा जा सकता है, इसके रूप में वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य बताने के लिए संबद्ध देशों/प्रदेशों से पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

13. जांच की शुरुआत का औचित्य बताने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं जिससे कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जिसे अगर लगाया गया हो घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य बताता है। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा इस नियमावली के पैरा 5 के संबंध में घरेलू उद्योग को कथित पाटन और परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं।

### जांच की अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि जनवरी, 2019 से सितंबर, 2019 (9 माह) है। हालांकि क्षति की जांच की अवधि में 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में इसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, इस उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित रूप में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए पृथक् रूप से पत्र लिखा जा रहा है।

### निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### व्यापार उपचार महानिदेशालय

#### वाणिज्य विभाग

#### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

#### चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

#### 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाला किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

### समय सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। हालांकि यह भी नोट किया जाए कि उक्त उप नियम की व्याख्या के संबंध में, यह माना जाएगा कि सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस उस तिथि जिस तिथि को इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजा गया था, अथवा संप्रेषित किया गया था, से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है तब प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समयसीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

### **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा किया गया हो तब उसे दो अलग अलग सैटों (क) एक सैट पर (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) गोपनीय अंकित होना चाहिए तथा (ख) दूसरे सैट पर (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) अगोपनीय अंकित हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दी गई सभी सूचना पर अनिवार्यतः प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से या तो “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में अंकित होना चाहिए।

21. इस प्रकार गोपनीय के रूप में अंकित किए बिना दी गई सूचना को अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय पाठ की 4 (चार) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की 2 (दो) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

22. गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना के लिए, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है और/अथवा क्यों इस प्रकार की सूचना का सारांश संभव नहीं है।

23. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानतः इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

24. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाली इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

25. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

26. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

### **असहयोग**

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी इस प्रकार के हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी के रूप में घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस.भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2019

**Case No. (O.I.) 21/2019**

**Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycol” originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE and Singapore.**

**F. No. 6/29/2019-DGTR.**—Whereas M/s Reliance industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application on behalf of domestic industry before Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)” (hereinafter referred as “product under consideration” or “subject goods”) originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE and Singapore (also referred to as “subject countries”).

**Product under consideration**

2. The product under consideration (PUC) is “Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)”. It is a clear, colourless, virtually odourless, and slightly viscous liquid. The subject good is used to produce polyester fibres, polyester films, and resins. It is also used in the fibre treatment of textiles, the paper industry, and in adhesives, inks, and cellophane. It is also used as a dehydration agent in natural gas pipelines where it inhibits the formation of natural gas clathrates before being recovered from the gas and reused.

3. MEG is classified under the tariff custom classification 2905 31 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

**Like article**

4. The applicant has claimed that the subject goods produced by them are like article to the subject goods originating in or exported from subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from subject countries. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like article’ of the subject goods imported from subject countries.

**Domestic industry and standing**

5. The application has been filed by M/s Reliance Industries Limited (RIL) on behalf of domestic industry. It is also noted that M/s. India Glycols Limited has supported the present petition. It is also noted that M/s. Reliance Industries Limited (RIL), has imported low volume of imports of PUC during period of investigation (POI) due to periodic catalyst change out which requires complete plant shut down and to support local market.

6. The matter has been examined. Considering the small volume of imports by the Reliance Industries Limited, the Authority has considered M/s. Reliance Industries Limited as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

**Countries involved**

7. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE and Singapore.

**Normal value**

8. The applicant has submitted that particular market situation exists in Kuwait, Oman, Saudi Arabia and UAE as producers get basic feedstock at differential and discounted prices. Due to the distorted prices of raw material, the applicant claimed that such prices cannot be considered for determination of normal value as they do not reasonably reflect the costs associated with the production of the subject goods. Accordingly, the applicant has claimed that the cost of raw material should be benchmarked to international prices.

9. For the purpose of initiation, the normal value for Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and UAE has been constructed on the basis of international price of its major raw material (Ethylene) and conversion cost of the domestic industry, with

reasonable addition for profits. The normal value for Singapore has been computed on the basis of Asia Pacific prices available in ICIS published report.

#### **Export price**

10. The applicant has claimed export price on the basis of DGCI&S published import data. The net ex-factory export price has been determined after due adjustments towards ocean freight, marine insurance, port expenses, commission and inland freight expenses.

#### **Dumping margin**

11. The normal value has been compared with export price at ex-factory level. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, showing that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters of the subject countries. The dumping margin as determined is above de minimis.

#### **Evidence of injury and causal link**

12. The petitioners have claimed that domestic industry has suffered material injury by way of adverse price effects as evidenced by price undercutting and price depression leading to accumulation of inventories, deterioration in profits, decline in return on capital employed and cash profits. The petitioners have claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject countries. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of material injury caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries/territory to justify initiation of an anti-dumping investigation.

13. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries to justify initiation of investigation.

#### **Initiation of Anti-Dumping Investigation**

14. The Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

#### **Period of Investigation (POI)**

15. The period of investigation for the purpose of the present investigation is January 2019 to September 2019 (9 months). The injury investigation period shall, however, cover 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.

#### **Submissions of information**

16. Known exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Trade Remedies**  
**Department of Commerce**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building,**  
**5 Parliament Street, New Delhi – 110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### **Time limit**

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated

Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on non-confidential basis**

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response / submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Four (4) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority